International Journal of Education and Science Research Review
E-ISSN 2348-6457
Volume-9, Issue-5 Sep - Oct – 2022
P-ISSN 2349-1817
www.ijesrr.org Email- editor@ijesrr.org

भारतीय उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र की भूमिका

Neera Kumari
Research scholar
Dept. Of Education, OPJS University, Churu, Rajasthan.

Dr. Suman Sharma
Associate professor
OPJS University, Churu, Rajasthan

सार

भारत के गणतंत्र बनने के बाद से पहले 50 वर्षों के लिए, इसका शिक्षा क्षेत्र परंपरागत रूप से मूल सिद्धांत पर बनाया गया है कि यह राज्य की जिम्मेदारी है कि वह अपने नागरिकों को शिक्षित करे। इस उद्देश्य की दिशा में, पिछले दो दशकों में नीतिगत फोकस का एक महत्वपूर्ण पहलू क्षमता निर्माण पर रहा है।

सरकार ने नई क्षमताएं सृजित करने के साथ–साथ मौजूदा संस्थानों में उन्हें बढ़ाने के लिए निवेश करना जारी रखा है। प्रगति की गई है भारत निश्चित रूप से 2010–11 में 28 विश्वविद्यालयों और 578 कॉलेजों से 500 से अधिक विश्वविद्यालयों और वर्तमान में 25,000 से अधिक कॉलेजों तक एक लंबा सफर तय कर चुका है। आज, देश में दुनिया में सबसे अधिक उच्च शिक्षा संस्थान हैं और करीब 20 मिलियन छात्र नामांकित हैं।

उच्च शिक्षा के प्रति वर्तमान दृष्टिकोण 2016 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) और 2012 की कार्रवाई के कार्यक्रम द्वारा शासित है। दो ऐतिहासिक रिपोर्ट, राधाकृष्णन आयोग की रिपोर्ट (2018–49) और कोठारी आयोग की रिपोर्ट (2014–66), वास्तव में देश में उच्च शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति के लिए बुनियादी ढांचा निर्धारित किया। एनपीई दस्तावेज इस तथ्य को स्वीकार करता है कि श्उच्च शिक्षा को पहले की तरह गतिशील बनना होगाश और इस प्रभाव के लिए स्वायत्तता, विशेषज्ञता, व्यवसायीकरण, अनुसंधान और विकास पर जोर देने सहित कई कदमों की रूपरेखा तैयार की गई है।

परिचय

भारत की आजादी के 62 साल बाद भी, सभी प्रगति के लिए, उच्च शिक्षा पहुंच, इक्विटी और गुणवत्ता के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करती है।

वर्तमान में 15–35 वर्ष आयु वर्ग की आबादी 350 मिलियन से अधिक है, जिसके 2030 ख्8, में लगभग 485 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। इतनी बड़ी संख्या में सस्ती, अच्छी गुणवत्ता, विश्व स्तर पर प्रासंगिक उच्च शिक्षा प्रदान करना इस देश के सामने सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। जब तक यह अपने कार्य को एक साथ करने और तंत्र की एक विस्तृत श्रृंखला

को स्थापित करने में सक्षम नहीं होता है, तब तक भारत उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं की सुनामी को घूर रहा होगा और प्रणाली में मांग को पूरा करने की क्षमता नहीं होगी। ऐसी स्थिति, भारत के योजना आयोग के सदस्य, नरेंद्र जाधव के शब्दों में, श्जनसांख्यिकीय आपदा की ओर ले जाएगी, सिर्फ खाने के लिए मुंह जोड़ना, काम करने वाले हाथ नहींश (यह बयान भारतीय राज्य विश्वविद्यालय की बैठक में दिया गया था।

मामले को बदतर बनाते हुए, राज्यों, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों, लिंग और समुदायों में उच्च शिक्षा सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में व्यापक असमानता है। अर्न्स्ट एंड यंग–फिक्की (2011) के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में जीईआर 23.8 प्रतिशत है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 7.5 प्रतिशत कम है। दिल्ली का जीईआर 31.9 प्रतिशत है जबकि असम 8.3 प्रतिशत से पीछे है।

भारत पहले से ही अमीर–गरीब और ग्रामीण–शहरी विभाजन से जूझ रहा है। शिक्षा शायद अमीरों और वंचितों के बीच की खाई को पाटने का सबसे अच्छा साधन हो सकती है। फिर भी, जैसा कि इन आंकड़ों से पता चलता है, शिक्षा तक पहुंच में स्पष्ट असमानताएं हैं जो समाज में विभाजन को और बढ़ा देती हैंख्9,।

राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (छ।।ब्) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों में बार–बार इस बात पर जोर दिया गया है कि अधिकांश उच्च शिक्षा संस्थान राजस्थान में शैक्षणिक और भौतिक बुनियादी ढांचे की कमी के मामले में एक गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। नवाचार की कमी, निरर्थक पाठ्यक्रम, सिद्धांत पर अधिक जोर, अनुसंधान और सामाजिक विज्ञान के लिए कम महत्व, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को प्रेरित नहीं करना, और शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता की निगरानी नहीं होना इस तरह की निराशाजनक स्थिति के प्रमुख कारण हैं।

तथ्य यह है कि ज्यादातर कंपनियों को नए स्नातकों को प्रशिक्षण देने के लिए भारी मात्रा में समय और पैसा खर्च करना पड़ता है, इसे उद्योग की चाहत और उच्च शिक्षा संस्थानों से निकलने वाले आउटपुट की गुणवत्ता के बीच कौशल–निर्धारित अंतर के एक संकेतक के रूप में देखा जा सकता है। इन सभी वर्षों में, सरकारों ने मुख्य रूप से क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया है। एनपीई दस्तावेज, शायद इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि मौजूदा संस्थानों की गुणवत्ता पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, प्रस्तावित करता है कि शनिकट भविष्य में, मुख्य जोर मौजूदा संस्थानों के समेकन और सुविधाओं के विस्तार पर होगा। श्ख10,। भारतीय उच्च शिक्षा निस्संदेह बड़ी चुनौतियों का सामना करती है।

जहाँ एक ओर अधिक से अधिक युवाओं को उच्च शिक्षा के दायरे में लाने की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर भवन निर्माण की गुणवत्ता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता पर महत्वपूर्ण रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। शिक्षा की गुणवत्ता का रोजगार और श्रम उत्पादकता पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, भारत की श्रम शक्ति, जो 2016 में 472 मिलियन थी, 2031 में लगभग 653 मिलियन होने की उम्मीद है। भारत की विकास गाथा मुख्य रूप से इसके सेवा क्षेत्र द्वारा संचालित है जो बदले में कुशल श्रम शक्ति से शक्ति प्राप्त करता है। जब तक देश के पास तेज–तर्रार गतिशील उच्च शिक्षा

प्रणाली नहीं है, तब तक यह न केवल चीन और ब्राजील बल्कि फिलीपींस और मलेशिया जैसे छोटे देशों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक लाभ खोने के खतरे का सामना करता है।

सरकार भारत की उच्च शिक्षा चुनौतियों का सभी समाधान प्रदान नहीं कर सकती है। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में उच्च शिक्षा पर भारत का सार्वजनिक व्यय 0.6 प्रतिशत है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस), यूनाइटेड किंगडम (यूके) और चीन जैसे अन्य देशों द्वारा प्रति छात्र आधार पर खर्च किए जाने से कम है। . उच्च शिक्षा पर अधिकांश सार्वजनिक व्यय राजस्थान में मौजूदा संस्थानों के वेतन और रखरखाव पर खर्च किया जाता है।

उच्च शिक्षा पर केंद्र सरकार के खर्च का अधिकांश हिस्सा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) (लगभग 40 प्रतिशत) को आवंटित किया जाता है, जो मुख्य रूप से उनके रखरखाव और विकास के लिए अनुदान के रूप में कॉलेजों की सहायता करता है। पाठ्यक्रम, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी पर बहुत कम खर्च किया जाता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) जैसे कुछ ही संस्थान औसत दर्जे के समुद्र के बीच उत्कृष्टता के प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़े हैं। इन संस्थानों में प्रवेश की विशेषता एक पागल भीड़ है जो उम्मीदवारों के बीच अत्यधिक तनाव का कारण बनती है ख1,।

भारतीय उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र की भूमिका

पिछले दो दशकों में, तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था ने शिक्षित और कुशल श्रम शक्ति की भारी मांग को जन्म दिया है। एक गतिशील अर्थव्यवस्था की जनशक्ति की जरूरतों को पूरा करने के लिए, आश्चर्य की बात नहीं, निजी उद्यम सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों के पूरक के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि वे क्षमता की कमी से ग्रस्त हैं। वास्तव में, पिछले कुछ दशकों में, यह निजी क्षेत्र रहा है जिसने वास्तव में भारतीय उच्च शिक्षा में क्षमता निर्माण को प्रेरित किया है।

भारत सरकार (जीओआई) और राज्यों द्वारा निवेश को कम करने के साथ, उच्च शिक्षा में निजी कॉलेज की उपस्थिति को 2010 के मध्य से बढ़ावा मिला। 2011 में, जब सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में 42.6 प्रतिशत निजी गैर–सहायता प्राप्त संस्थान थे, तब 32.8 प्रतिशत भारतीय छात्र वहां पढ़ते थे।

2014 तक, निजी संस्थानों की हिस्सेदारी 63.2 प्रतिशत हो गई और उनके छात्रों की हिस्सेदारी 51.5 प्रतिशत हो गई। इंजीनियरिंग और मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए) जैसे उच्च शिक्षा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उच्च शिक्षा का निजीकरण विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है, जहां ऐसे कार्यक्रमों की पेशकश करने वाले अधिकांश संस्थान निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित किए गए हैं। इतना ही, फार्मेसी और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में निजी संस्थानों की हिस्सेदारी 90 फीसदी से भी ज्यादा है. इन आँकड़ों से पता चलता है कि निजी शिक्षा खिलाड़ी अपवाद के बजाय आदर्श हैं और उच्च शिक्षा का निजीकरण अब राजस्थान में एक अपरिवर्तनीय प्रवृत्ति है। आलोचकों का तर्क है कि शिक्षा एक सामाजिक अच्छाई है और इसे विशेष रूप से

सरकार के हाथों में रहना चाहिए, इससे असहमत होना मुश्किल होगा कि भारतीय उच्च शिक्षा चुनौतियों के पैमाने और जटिलता को देखते हुए, सरकार अपने दम पर सभी मुद्दों से निपट नहीं सकती है। .

यह कहना नहीं है कि निजीकरण भारत की सभी उच्च शिक्षा समस्याओं का रामबाण इलाज है। वास्तव में, इस परिघटना ने अपने स्वयं के मुद्दों और चुनौतियों को जन्म दिया है। फिर भी, तथ्य यह है कि भारत में एक बढ़ती युवा आबादी है जो शिक्षा को समृद्धि के टिकट के रूप में देखती है, साथ ही सरकार द्वारा शिक्षा खर्च में गिरावट के साथ, निजी उच्च शिक्षा की एक बड़ी मांग में तब्दील हो जाती है। उच्च शिक्षा, विशेष रूप से व्यावसायिक शिक्षा की भारी मांग के बावजूद, मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन (एमएजीई) सर्विसेज ने भारत में अपनाए जाने वाले पारंपरिक ईंट और मोर्टार कैंपस मॉडल से दूर रहने का एक सचेत निर्णय लिया है। इसके बजाय उन्होंने यहां एक शिक्षा सेवा व्यवसाय बनाने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है।

निश्चित रूप से, तेजी से बढ़ते निजीकरण ने सार्वजनिक कॉलेजों पर दबाव कम किया है, लेकिन उनके सबसे उत्साही समर्थकों को भी यह दावा करना मुश्किल होगा कि निजी संस्थानों ने पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति, अनुसंधान और विकास और सीखने के परिणामों में काफी सुधार किया है।

यह इस तथ्य पर विचार करते हुए आश्चर्यजनक नहीं है कि उच्च शिक्षा अभी भी अर्थव्यवस्था में सबसे सख्त विनियमित क्षेत्रों में से एक है। उच्च शिक्षा में निजीकरण एक उलझी हुई कहानी है, जिसमें कुछ लोग तर्क देते हैं कि भारतीय उच्च शिक्षा श्आधे–पके समाजवाद से आधे–अधूरे पूंजीवादश में बदल गई है।

राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं (आईटी और आईटीईएस), दूरसंचार, बैंकिंग, आदि जैसे क्षेत्रों को बदलने में निजी उद्यम द्वारा निभाई गई भूमिका स्पष्ट है। आज इसकी विकास गाथा ने भारत को वैश्विक आर्थिक मानचित्र पर ला खड़ा किया है। ये क्षेत्र उस प्रगति के चमकदार उदाहरण हैं जो निजी उद्यम को मुक्त और उत्साहजनक तरीके से कार्य करने की अनुमति देकर की जा सकती है। दुर्भाग्य से, उच्च शिक्षा संचालन वातावरण कुछ चुनौतियां प्रदान करता है जो गंभीर खिलाड़ियों को क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकता है। निम्नलिखित खंडों में, उच्च शिक्षा में एक गतिशील, संपन्न निजी उद्यम के लिए जिन मुद्दों को हल करने की आवश्यकता है, उन पर प्रकाश डाला गया है।

भारत में एक उच्च शिक्षा संस्थान केवल एक ट्रस्ट या एक सोसायटी द्वारा स्थापित किया जा सकता है। नीति–निर्माता उच्च शिक्षण संस्थानों को लाभकारी कॉर्पोरेट संस्थाओं के रूप में स्थापित करने का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा एक सार्वजनिक वस्तु है और इसलिए इसे वाणिज्य के दायरे से बाहर होना चाहिए। जैसा कि पहले देखा गया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) की सभी नीतियां 2016 के एनपीई पर आधारित हैं। राजनीति की समाजवादी संरचना को देखते हुए, एनपीई 2016 में सामाजिक भलाई का मजबूत आधार हैय आश्चर्य की बात नहीं है, मुनाफा कमाना सख्त नहीं है। हालांकि, भारत के कई कॉलेज और विश्वविद्यालय निजी और सार्वजनिक दोनों ही संकायों की भारी कमी, खराब सुसज्जित पुस्तकालयों, पुराने पाठ्यक्रम और खराब बुनियादी ढांचे का सामना करते हैं।

एक अच्छे शिक्षण संस्थान के निर्माण के लिए बड़े भौतिक और सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी और रिसर्च। अन्य क्षेत्रों में बढ़ते बाजार संचालित वेतन के युग में, अगर प्रतिस्पर्धी मुआवजे का भुगतान नहीं किया जाता है तो प्रतिभा को आकर्षित करने और बनाए रखने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? इन सभी के लिए बहुत अधिक वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। जमीन की बढ़ती दरें निवेश को फिर से हासिल करना और भी मुश्किल बना देती हैं।

इसलिए, यह अनिवार्य है कि शैक्षिक उद्यमों की प्रतिमोच्य पूंजी तक पहुंच हो, जो क्षेत्र के श्नॉट–फॉर–प्रॉफिटश ढांचे को देखते हुए लगभग असंभव हो जाता है। समय की मांग है कि संस्थागत वित्त पोषण वाले गंभीर खिलाड़ियों को आकर्षित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए जो इस क्षेत्र में प्रवेश कर सकें और पारदर्शी और उच्च गुणवत्ता वाले संस्थानों का निर्माण कर सकें। इसमें कोई संदेह नहीं है कि श्लाभ के लिए नहींश संरचना के पीछे मंशा नेक हो सकती है, फिर भी एक सवाल पूछने की जरूरत है कि क्या यह वांछित उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। इसके विपरीत, यह वास्तव में इसके लिए बेहतर हो सकता है कि उच्च शिक्षा में वैध लाभ की अनुमति दी जाए और ट्यूशन आय पर सेवा कर और संस्थानों द्वारा किए गए अधिशेषों पर आयकर से राजस्व प्राप्त किया जाए। इन कॉर्पोरेट शिक्षा संस्थाओं से की गई आय को शिक्षा में वापस लगाया जा सकता है। फायदे के मकसद से अलग–अलग जरूरतों के लिए अलग–अलग मॉडल बनाने के लिए वैकल्पिक पूंजी को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्थानांतरित करने की अनुमति मिलेगी। वास्तव में वर्तमान संरचना गंभीर उद्यमियों को इस क्षेत्र में अपनी इक्विटी लगाने से रोकती है। इसका मतलब है, एकमात्र सहारा ऋण है जो दबाव बढ़ाता है और एक तरह से प्रवेश अवरोध पैदा करता है।

इसमें पर्याप्त खामियां हैं जो बड़े पैमाने पर मुनाफाखोरी को अंजाम देती हैं। यह वास्तव में विडंबना है कि सभी नियम वास्तव में उन खिलाड़ियों को बाहर रखने में कामयाब नहीं हुए हैं जो शिक्षा को केवल संभावित उच्च प्रतिफल वाले व्यवसाय के रूप में देखते हैं। इस देश में राजनीतिक वर्ग के संदिग्ध वर्ग द्वारा चलाए जा रहे कई निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों जैसे तथ्यों से सामना होने पर किसी को आश्चर्य नहीं होता है

व्यवस्था कोई भी हो उसमें जवाबदेही होनी चाहिए, जो फिलहाल ट्रस्टों के मामले में नहीं है। यह नोट करना कुछ हद तक संतुष्टिदायक है कि योजना आयोग का 12 वीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज स्पष्ट रूप से क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान देने से ध्यान हटाकर अधिक सूक्ष्मता पर जोर देता है जो गुणवत्ता को सामने रखता है। यह परिवर्तन सार्वजनिक और निजी दोनों तरह की सर्वश्रेष्ठ भारतीय उच्च शिक्षा संस्थाओं को समय–समय पर वैश्विक मानकों के साथ संरेखित करने की अनुमति देगा, जबकि संस्थानों में लगातार सुधार के लिए कई स्तरों पर स्पष्ट दबाव पैदा करेगा।

विचार विमर्श

राज्य स्तर पर उच्च शिक्षा नेतृत्व और प्रबंधन में रणनीतिक जुड़ाव और क्षमता निर्माण के अवसर हैं। भारत के लिए गुणवत्ता आश्वासन, अंतर्राष्ट्रीय ऋण मान्यता और एकीकृत राष्ट्रीय योग्यता ढांचे सहित प्रणालीगत सुधार के क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करने के अवसर हैं। उच्च शिक्षा में शैक्षिक अवसर की समानता को इसलिए आवश्यक माना जाता है क्योंकि उच्च शिक्षा आय और धन की असमानताओं को कम करने या समाप्त करने का एक शक्तिशाली उपकरण है।

शैक्षिक अवसरों को समान करने का विचार इस तथ्य में भी निहित है कि ष्उच्च शिक्षा द्वारा लाभ की क्षमता सभी वर्गों के लोगों में फैली हुई है। समाज में अप्रयुक्त क्षमता के महान भंडार हैंय मौका दिया जाए तो वे शीर्ष पर पहुंच सकते हैं। वास्तव में, उच्चतम स्तर की प्रतिभा का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा की एक असमान प्रणाली द्वारा खो गया हैष्। स्नातकों की रोजगार क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता उद्यम शिक्षा और उद्यमिता में सहयोग के लिए प्रवेश बिंदु, उद्योग के साथ संबंध, अनुसंधान कौशल और अंग्रेजी सहित हस्तांतरणीय कौशल की विस्तृत श्रृंखला पेश कर रही है।

व्यावसायिक कौशल बाजार में भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों में उभरती दिलचस्पी अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ संभावित जुड़ाव के लिए क्षेत्र प्रदान करती है। मंचों (सम्मेलनों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों) में समर्थन और भागीदारी बढ़ाकर उच्च शिक्षा में मजबूत संबंध बनाने और आपसी समझ बढ़ाने की आवश्यकता है जो दुनिया के अन्य देशों के साथ बहस और संवाद को सक्षम बनाता है।

निष्कर्ष

कार्यों और अधिदेशों के ओवरलैप के साथ कई नियामक एजेंसियां उच्च शिक्षा संस्थान के कामकाज के लगभग हर पहलू को नियंत्रित करती हैं। एक निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता होती है। जब तक कोई निजीध्डीम्ड विश्वविद्यालय स्थापित नहीं करता है, डिग्री प्रदान करने में सक्षम होने के लिए, कॉलेजों को मौजूदा विश्वविद्यालयों के साथ श्संबद्धश होना होगा और मौजूदा मानदंडों का पालन करना होगा। अपने वर्तमान स्वरूप में संबद्धता की प्रणाली एक विश्वविद्यालय द्वारा एक कॉलेज के व्यक्तिगत कामकाज पर अत्यधिक नियंत्रण की ओर ले जाती है। मान्यता प्राप्त कॉलेज को भर्ती और पाठ्यक्रम से लेकर फैकल्टी और परीक्षाओं तक लगभग हर पहलू पर विश्वविद्यालय की लाइन का पालन करना पड़ता है।

ग्रंथ सूची

1. रिपोर्ट टू द नेशन 2016–2019, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, मार्च 2019
2. उच्च शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सीएबीई) समिति की रिपोर्टष्, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जून 2015,
3. ष्उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2013–14 (अनंतिम), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 2015,

4. विप्लव शर्मा बनाम भारत संघ व अन्य, 2016 की रिट याचिका (सिविल) 142।

5. उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2012–13 (अनंतिम), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 2015

6. अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ व अन्य, 2016 की रिट याचिका सिविल

7. प्रमति शैक्षिक और सांस्कृतिक ट्रस्ट और अन्य। बनाम भारत संघ व अन्य, 2012 की रिट याचिका